केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बनाम

मेसेर्स अरिहंत थ्रेयड्स लिमिटेड और अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 5225)

27 अक्टूबर, 2014

[एच. एल. दत्तू, सीजेआई, एस. ए. बोबडे आनंदभाई मनोहर सप्रे, जे. जे.]

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 -धारा 22-बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 -धारा 34-दो अधिनियमों की व्याख्या-दोनों अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम दोनों विधानों में गैर-अबाधित खंड को देखते हुए प्रबल होगा -एस. आई. सी. ए. के प्रावधान, विशेष रूप से एस.22, आर. डी. डी. बी. अधिनियम में ऋणों की वसूली के प्रावधान पर प्रबलता होगी-दोनों अधिनियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग-अलग डी है और जहां दोनों कानूनों के तहत कार्रवाई विरोधाभासी प्रतीत हो सकती है, संसद ने एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही को विशेष रूप से उप-धारा (2) के लिए प्रावधान करके बुद्धिमानी से संरक्षित किया है, जो यह निर्धारित करता है कि बाद का अधिनियम आर. डी. डी. बी. एस. आई. सी. ए. के अतिरिक्त होगा न कि अपमान में।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1.1 बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 दोनों अधिनियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। एक का उद्देश्य बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए सुधारात्मक उपाय प्रदान करना है, और दूसरे का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की शीघ्र वसूली प्रदान

करना है।दोनों अधिनियम इस मायने में "विशेष" हैं।हालाँकि, बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण के विशिष्ट उद्देश्य के संदर्भ में, एस. आई. सी. ए. को एक विशेष कानून माना जाना चाहिए, हालाँकि इसे ऋणों की वसूली के संबंध में एक सामान्य कानून माना जा सकता है।जबकि, आर. डी. डी. बी. अधिनियम को 1097 ऋणों की वसूली के संबंध में एक विशेष कानून माना जा सकता है और एस. आई. सी. ए. को एक सामान्य कानून माना जा सकता है। इस संबंध में कानून।आम तौर पर दोनों में से उत्तरार्द्ध इस सिद्धांत पर प्रबल होगा कि विधानमंडल को पता था कि उसने पहले के अधिनियम को अधिनियमित किया था और फिर भी एक गैर-अबाधित खंड के साथ बाद के अधिनियम को अधिनियमित करने का विकल्प चुना।तत्काल मामले उक्त लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.1) के आधार पर पुलिस थाना सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर में धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया। जाँच श्री शंकर बक्स सिंह, सहायक उपनिरीक्षक को सौंपी गयी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, एक्सप्रेस।आर. डी. डी. बी. अधिनियम के गैर-अस्थाई खंड में संसद का इरादा उस दृष्टिकोण को लेने की अनुमति नहीं देता है।यद्यपि आर. डी. डी. बी. अधिनियम बाद का अधिनियमन है, खंड 34 की उप-खंड (2) विशेष रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधान एस. आई. सी. ए. सहित उसमें उल्लिखित अन्य कानूनों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अपमान में। (पैरा.49)(1120-सी-एच]

1.2 "अपमान में नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों को किसी भी तरह से कम करने या निराकृत होना नहीं करने के संसद के इरादे को व्यक्त करता है।वास्तव में इसका मतलब यह होना चाहिए कि संसद का इरादा एक बीमार कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही जारी रखने का था और उस उद्देश्य के लिए आगे यह इरादा था कि कंपनी और उसकी संपत्तियों के खिलाफ

अन्य सभी कार्यवाही को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तक रोक दिया जाना चाहिए।जबकि खंड 22 के तहत "कार्यवाही" शब्द में मूल रूप से आर. डी. डी. बी. अधिनियम शामिल नहीं था, जो अस्तित्व में नहीं था।खंड 22 आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत कार्यवाही को शामिल करती है। [पैरा ~ 0) (1121-ए-सी]

1.3 दोनों अधिनियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है और जहां दोनों कानूनों के तहत कार्रवाई विरोधाभासी प्रतीत हो सकती है, संसद ने एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही को बुद्धिमानी से संरक्षित किया है, विशेष रूप से उप-धारा (2) के लिए प्रावधान करके, जो यह निर्धारित करता है कि बाद का अधिनियम आर. डी. डी. बी. एस. आई. सी. ए. के अतिरिक्त होगा न कि अपमान में। कि यह निष्कर्ष व्याख्या के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माने जाने वाले सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है अर्थात के इरादे को प्रभाव देना।विधायिका।कठिनाई पैदा हो गई।मुख्य रूप से एस. आई. सी. ए. की खंड 22 को लागू करते समय आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत ऋणों की वसूली के लिए आवेदनों को शामिल करने के लिए संसद के इरादे को दर्शाने वाले विशिष्ट शब्दों की अनुपस्थिति में के कारण। इस अभावि का स्पष्ट कारण यह तथ्य है कि एस. आई. सी. ए. पहले अधिनियमित किया गया था।यह कर्तव्य है

आर. डी. डी. बी. अधिनियम के अधिनियमन के बाद एस. आई. सी. ए. पर विचार करने के लिए न्यायालय यह प्रावधान करने के सही इरादे और उद्देश्य का पता लगाने के लिए कि निष्पादन या बाधाओं या मुकदमों के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी या आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।निस्संदेह, संकीर्ण अर्थों में ऋण की वसूली के लिए एक आवेदन एक सीमित अर्थ दे सकता है अर्थात एक कार्यवाही जो दाखिल करने पर शुरू होती है और निर्णय पर समाप्त होती है।हालाँकि, सु देने की कोई आवश्यकता नहीं है।च एक प्रतिबंधित अर्थ है, क्योंकि पुनर्प्राप्ति के लिए एक आवेदन का वास्तविक उद्देश्य निष्पादन और पुनर्प्राप्ति के तार्किक अंत तक आगे बढ़ना है, जो कि निष्पादन और बाधा

के माध्यम से है।इस प्रकार,धारा 22 स्पष्ट रूप से प्रावधानों के तहत की गई वसूली के लिए ऐसे डी आवेदन को शामिल और बाधित करती है। आरओबी अधिनियम। इसके अलावा, एस. आई. सी. ए. के खंड 22 के दायरे से वसूली आवेदन को बाहर करने के इरादे में कुछ भी विपरीत नहीं पाया गया है, वास्तव में इस तरह के बहिष्कार का कोई कारण नहीं हो सकता है क्योंकि प्रावधान का उद्देश्य है।एक बीमार कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करें, ताकि बी. आई. एफ. आर. द्वारा इसके पुनरुद्धार के उद्देश्य से उनसे सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटा जा सके। [पारस 51,52,53] [1121-सी-एच; 1122-ए-बी; 1122-जी-एच; 1123-ए]

1.4 एस. आई. सी. ए. के प्रावधान, विशेष रूप से खंड 22, आर. डी. डी. बी. अधिनियम में ऋणों की वसूली के प्रावधान पर हावी होंगे। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।जहाँ तक रिट याचिकाओं का संबंध है, चाहे इस आधार पर कि एस. आई. सी. ए. की खंड 22 आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत वसूली जी कार्यवाही के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है या क्या आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही समाप्त होने के बाद से अपीलकर्ता कंपनी को एस. आई. सी. ए. का संरक्षण उपलब्ध नहीं है, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।[पैरा 54] [1123-डी-एफ]

कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य. वी.यू. पी. लिमिटेड का प्रदेशिया औधोगिक और निवेश निगम और एन. आर. 2003 (1) एससीआर 1159:(2003) 4 एस. सी. सी. 305; राम नारायण बनाम शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड 1956 एससी 614:1956 एससीआर 603; यू. सी. बनाम. डी. जे. बी बहादुर 1981 (1) एससीआर 1083 = (1981) 1एससीसी315; महाराष्ट्र ट्यूब लिमिटेड बनाम।राज्य औद्योगिक और निवेश निगम।महाराष्ट्र लिमिटेड 1993 (1) एस. सी. आर. 340:(1993) 2 एससीसी 144; इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक 2000 (2) एससीआर 1102:

(2000) 4 सी एस. सी. सी. 406; भारतीय रिजर्व बैंक अन्य पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य। 1987 (2) एससीआर 1:(1987) 1 एस. सी. सी. 424; पंजाब राज्य बनाम ओकारा अनाज खरीदार सिंडिकेट लिमिटेड 1964 एस. सी. आर. 387:ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 669-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

2003 (1) एस. सी. आर. 1159	संदर्भित है	पैरा 30
1956 एस. सी. आर. 603	निर्दिष्ट है	पैरा 43
1981 (1) एस. सी. आर. 1083	निर्दिष्ट है	पैरा 45
1993 (1) एस. सी. आर.340	संदर्भित	पैरा 46
2000 (2) एस. सी. आर. 1102	संदर्भित	पैरा47
1987 (2) एस.सी.आर.1	उल्लेख किया	पैरा 52
1964 एस. सी. आर. 387	संदर्भित	पैरा 53

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी याचिका सं. 5225/2008

उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली के 2006 के सिविल रिट याचिका सं. 2041 तथा 2042 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 23-02-2006 से।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, आरोही भल्ला (सुश्री सुजाता कुर्दुकर के लिए) अधिवक्ता।अपीलकर्ता के लिए।

सीए सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय चौधरी, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत, गोविंद ग्रेवाल, दशरथ टी. एम., पुनीत दत्त के. त्यागी, संजय भट, दुष्यंत कुमार (रबीन मजूमदार के लिए) ए राजेश शर्मा (सुश्री शालू शर्मा के लिए) अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय एस. ए. बोबडे, जे. द्वारा पारित किया गया

1. यह अपील हमारे समक्ष एक संदर्भ के माध्यम से रखी गई है, जो इस न्यायालय की दो- न्यायाधीशों की पीठ, सी. के. ठक्कर और अल्तमस कबीर, जे. जे. द्वारा की गई थी, जिसने पहले एक अवसर पर मामले की सुनवाई की थी और कहा था कि अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की खंड 34 की व्याख्या पर मतभेद उत्पन्न होने को देखते हुए (जिसे इसके बाद ऋण के रूप में संदर्भित किया गया है) आर. डी. डी. बी. अधिनियम) इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय के लिए इस पीठ को भेजा गया है।

2. वर्तमान अपील केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (संक्षिप्त में 'अपीलार्थी') द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की रिट याचिका संख्या 2041-2042 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.02.06 के खिलाफ की जाती है।उच्च न्यायालय ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली (संक्षेप में 'डी. आर. ए. टी.') द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद 'एस. आई. सी. ए.' के रूप में संदर्भित किया गया है) की खंड 22 में निहित प्रतिबंध को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 (एम/एस.) के खिलाफ कोई वसूली कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड) (संक्षेप में 'कंपनी')।

3. कंपनी ने पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में सूती धागे के निर्माण के लिए एक निर्यात उन्मुख कताई इकाई की स्थापना की। कंपनी ने 1992 में गोइंदवाल साहिब औद्योगिक और निवेश निगम से 99 साल की अवधि के लिए प्लॉट संख्या 454 पट्टे

पर लिया, इस शर्त पर कि वह पट्टेदार की पूर्व अनुमति के बिना पहले पंद्रह वर्षों तक संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण नहीं करेगी। कंपनी के पास ऋण की प्रतिभूति के रूप में बैंक, पंजाब वित्तीय निगम या भारतीय जीवन बीमा निगम को पट्टे पर रखने के अधिकार को गिरवी रखने का अधिकार था।इसने अपनी परियोजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संक्षेप में 'आईडीबीआई') द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया और इसकी कार्यशील पूंजी रु 93.1 करोड़।

4. चूंकि कंपनी ऋण किश्तों का भुगतान करने में विफल रही, इसलिए आई. डी. बी. आई. ने दिसंबर 2001 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (संक्षेप में 'डी. आर. टी.') में 1368 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मूल आवेदन संख्या 2001 दायर की। आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत 25,26,60,836/-। डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही में कंपनी अनुपस्थिति रही, हालांकि, विधिवत सेवा की 15.07.03 को , उपरोक्त राशि की वसूली के लिए आई. डी. बी. आई. के पक्ष में एक एकतरफा अंतिम आदेश अर्थात रु. डी. आर. टी. द्वारा 7.8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 25,26,60,836/- पारित किया गया। डीआरटी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि कंपनी की ओर से डिक्रीटल राशि का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, आईडीबीआई कंपनी की गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने और राशि की वसूली करने का हकदार होगा।यदि तब भी राशि की वसूली नहीं होती है, तो इसे प्रतिवादियों की व्यक्तिगत संपत्तियों की बिक्री से वसूल किया जाएगा।

5. 09.09.03 पर, वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत कंपनी के खिलाफ समग्र मांग नोटिस जारी किया, जिसमें कंपनी ने 28,60,87,384/ रुपये का भुगतान करने की मांग की। - उन्होंने कंपनी को बिक्री की घोषणा के नियमों और शर्तों के निपटारे और अपनी चल और अचल संपत्तियों के प्रकटीकरण के लिए पेश होने का निर्देश दिया।

6. 16.09.04 को, वसूली अधिकारी ने चल और अचल संपत्तियों का आरक्षित मूल्य रु 12.50 करोड़ तय किया। 18.10.04 पर, कंपनी ने आर. डी. डी. बी. अधिनियम की खंड 30 के तहत 16.09.04 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें चल और अचल संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 5 लाख रुपये तय किया गया था 12.50 करोड़। 30.10.04 को, अपीलकर्ता को रुपये में सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। 12.52 करोड़ और इस प्रकार सफल रहा। डी. आर. टी. चंडीगढ़ द्वारा आई.डी.बी.आई. के पक्ष में रुपये की वसूली का निर्देश 25,26,60,836/- ब्याज के साथ @7.8% प्रति वर्ष तय किया गया । अपीलकर्ता, जो कंपनी की संपत्तियों का नीलामी-खरीदार बन गया था, ने कंपनी की एकतरफा संपत्ति की प्रार्थना पर आपत्ति जताई।

आदेश दिया और अभियोग के लिए आवेदन किया। इस बीच, कंपनी ने अपनी संपत्ति का मूल्य हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया। कंपनी की संपत्ति का वास्तविक मूल्य रु 20.22 करोड़ पाया।

7. 26.07.05 को ORT-I, दिल्ली ने कंपनी के बी फिक्सेशन के खिलाफ आरडीडीबी अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील दायर की गई आरक्षित मूल्य रु. 12.50 करोड़. । नीलामी बिक्री से डीआरटी-I, दिल्ली, अलग रखा गया एक निश्चित राशि, ब्याज, व्यय, आदि

8. इन शर्तों पर आपत्ति जताते हुए कंपनी ने डी. आर. ए. टी., दिल्ली में एक अपील दायर की।अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में बिक्री को अलग रखने से व्यथित होकर एक अपील भी दायर की।डी. आर. ए. टी. ने उस दिनांकित 26.07.05 आदेश पर रोक लगा दी जिसके द्वारा कंपनी के खिलाफ एक तरफा आदेश को अलग कर दिया गया था और अपीलकर्ता को बिक्री राशि की वापसी का निर्देश दिया गया था।

9. 21.12.05 को, कंपनी ने एस.आई.सी.ए. के प्रावधानों को लागू किया। इसने औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (संक्षेप में 'बी. आई. एफ. आर.') के समक्ष एक संदर्भ दायर किया।10.02.06 को, डी. आर. ए. टी. ने कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया। डी.आर.ए.टी. ने बिक्री मूल्य जमा करने पर अपीलकर्ता के पक्ष में नीलामी-बिक्री की पुष्टि की। डी.आर.ए.टी. ने निर्देश दिया कि नीलामी-खरीदार (अपीलकर्ता) को संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए वसूली अधिकारी द्वारा कदम उठाए जाएं और अपीलकर्ता पूरी राशि जमा करेगा।

10. डी.आर.ए.टी. द्वारा निर्देशित औपचारिकताओं को पूरा करने से पहले, कंपनी ने डी. आर. ए. टी., दिल्ली के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर कीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के विवादित आदेश के माध्यम से रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और डी. आर. ए. टी., दिल्ली द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एस.आई.सी.ए. की खंड 22 के प्रतिबंध को देखते हुए, कंपनी के खिलाफ वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी और डी.आर.ए.टी., दिल्ली द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

11. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बी. आई. एफ. आर. ने कंपनी के संदर्भ को खारिज कर दिया और कंपनी ने एक अपील को प्राथमिकता दी, जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) के समक्ष लंबित है।दूसरा संदर्भ भी कंपनी द्वारा दायर किया गया है जिसे 2006 का बी.आई.एफ.आर. मामला संख्या 18 के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें कंपनी को 'बीमार' घोषित किया गया है।

कंपनी और प्रतिवादी संख्या 5 [तनावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष, मुंबई] को नियुक्त किया गया है पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए संचालन एजेंसी।

12. जैसा कि पहले कहा गया है, इस मामले की सुनवाई पहले इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। विद्वान न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति ठक्कर ने कहा कि आर.डी.डी.बी. अधिनियम के प्रावधानों को आर.डी.डी.बी. अधिनियम की खंड 34 के आधार पर एस.आई.सी.ए. पर प्राथमिकता और प्रधानता दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक बाद का अधिनियम है। इसलिए यह माना जा सकता है कि किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में में भी संसद सभी के बारे में जानती थी इससे पहले अधिनियमित कानून; कि गैर-अस्थाई खंड को शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों का न्यायनिर्णयन और वसूली।न्यायमूर्ति ठक्कर ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि आर. डी. डी. बी. अधिनियम की खंड 34 की उप-खंड (2) को ध्यान अन्य बातों के साथ साथ रखते हुए, जिसअन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान एस. आई. सी. ए. के अतिरिक्त हैं और इसके अपमान अन्य बातों के साथ साथ नहीं हैं, जो आर. डी. डी. बी. अधिनियम के प्रबल होने का एक अतिरिक्त कारण है।न्यायाधीश कबीर ने, उनके स्वामी के रूप में, यह अभिनिर्धारित किया कि खंड 34 (1) में गैर-अस्थाई खंड में एक अपवाद है, जो उप-खंड (2) में पाया जाता है।उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि अधिनियम एस. आई. सी. ए. के अतिरिक्त होगा और अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ उसका अपमान नहीं करेगा। इसके अलावा, आर. डी. डी. बी. अधिनियम का प्रबल प्रभाव अन्य अधिनियमों पर हावी होगा, लेकिन एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों के पूरक होगा, और इसलिए एस. आई. सी. ए. के प्रावधान एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों पर हावी होंगे। आरडीडीबीएक्ट के प्रावधान अधिनियम।

13. न्यायाधीश कबीर ने आगे कहा कि चूंकि कंपनी द्वारा एस. आई. सी. ए. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से पहले वसूली की कार्यवाही लंबे समय से समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कंपनी उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी राहत की हकदार नहीं होगी।

14. जे. कबीर ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया। केवल 21.12.05 पर ही कंपनी ने बी. आई. एफ. आर. के समक्ष एक संदर्भ दायर किया था जिसे 10.02.06 को खारिज कर दिया गया था। इससे पहले, वसूली अधिकारी ने आय आदेश अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत एक 28,60,87,384/ का मांग नोटिस जारी किया था। जैसा कि डी. आर. टी., चंडीगढ़ द्वारा अंतिम क्रम में निर्देशित किया गया है। इसके बाद, कई कार्यक्रम हुए, जैसे कि 27.10.2004 पर, डी. आर. टी. ने नीलामी बिक्री की अनुमति दी।

कार्यवाही लेकिन निर्देश दिया कि इसकी पुष्टि नहीं की जानी चाहिए; 30.10.04 पर, अपीलकर्ता को सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया था और उसने पूरे बिक्री मूल्य को 11.11.04 पर जमा कर दिया था; आर. डी. डी. बी. अधिनियम की खंड 30 के तहत अपील में, कंपनी ने आरक्षित मूल्य के निर्धारण के खिलाफ एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया और इस अपील को कुछ नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन 26.07.2005 पर अनुमति दी गई थी।यह देखा गया कि कंपनी द्वारा दायर अपील केवल आरक्षित मूल्य के निर्धारण के खिलाफ थी न कि अंतिम आदेश के खिलाफ।कंपनी ने आर. डी. डी. बी. अधिनियम की खंड 20 के तहत या आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 60 के तहत बिक्री को अलग करने के लिए अपील का भी लाभ नहीं उठाया था, लेकिन केवल इस आधार पर नीलामी-बिक्री को अलग रखने का रास्ता चुना था कि कंपनी की संपत्तियों का आरक्षित मूल्य सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया था।वास्तव में, आर. डी. डी. बी.

अधिनियम की खंड 19 के तहत आई. डी. बी. आई. के पक्ष में कार्यवाही बी. आई. एफ. आर. के आने से बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी।आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत संपत्तियों की नीलामी बिक्री की पुष्टि डी. आर. ए. टी. द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिकाओं की अनुमति देने से पहले की गई थी।

15. बी. आई. एफ. आर. द्वारा कंपनी के पहले संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया था और केवल 15.09.06 पर किए गए दूसरे संदर्भ की अनुमति दी गई थी, यानी उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.02.06 के आदेश के बाद।चूँकि वसूली की कार्यवाही अपीलकर्ता के पक्ष में समाप्त हो गई है और अपीलकर्ता ने बिक्री मूल्य भी जमा कर दिया है, इसलिए प्रत्यर्थी एस. आई. सी. ए. की खंड 22 के आधार पर किसी भी राहत का हकदार नहीं था।

16. इन परिस्थितियों में, दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने अलग-अलग कारणों से अभिनिर्धारित किया कि अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए। चूंकि, कानून के सवाल पर मतभेद था, इसलिए एक बड़ी पीठ का संदर्भ दिया गया था

बीमार औद्योगिक कंपनियों की योजना और उद्देश्य (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 [एस. आई. सी. ए.]

17. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित निर्धारित करता हैः यह व्याख्या करते हुए कि दो अधिनियमों में से कौन सा, अर्थात् बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 [एस. आई. सी. ए.] या बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 [आर. डी. डी. बी. अधिनियम] के कारण ऋणों की वसूली प्रबल होनी चाहिए, दोनों में निहित अबाधित खंड को देखते हुए, महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक दोनों अधिनियमों का

उद्देश्य है। यह पहचानना और सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दोनों अधिनियमों का उद्देश्य जहां तक संभव हो, पूरा हो।

18. एस. आई. सी. ए. को विशेषज्ञों के एक निकाय के समय पर निर्धारण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय जिन्हें बीमार कंपनियों को अपनाने की आवश्यकता होगी। औद्योगिक कंपनियों में बीमारी के दुष्प्रभाव जैसे उत्पादन का नुकसान, रोजगार का नुकसान, केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निवेश योग्य धन को बंद करना सरकार और बड़े पैमाने पर समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय था।उत्पादक औद्योगिक परिसंपत्तियों का पूरी तरह से उपयोग आदेशने के लिए, रोजगार की अधिकतम सुरक्षा प्रदान आदेशना और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के धन के इष्टतम उपयोग को पुनर्जीवित करना अनिवार्य पाया गया और संभावित रूप से बीमार औद्योगिक कंपनियों का पुनर्वास करना।

19. कानूनों और एजेंसियों की बहुलता ने बीमार औद्योगिक कंपनियों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाना मुश्किल बना दिया।निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के एक निकाय के समय पर निर्धारण के लिए कानून बनाने के लिए संसद में बीमार औद्योगिक कंपनी विधेयक पेश किया गया था।

20. जैसा कि इस मामले से संबंधित चीजों की योजना में महत्वपूर्ण प्रतीत होगा, बीमार औद्योगिक से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए "कानूनों और एजेंसियों की बहुलता" का एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया है कंपनियाँ मुश्किल हैं।

21. "बीमार औद्योगिक कंपनी" शब्द को एक औद्योगिक कंपनी (कम से कम पांच साल के लिए पंजीकृत कंपनी होने के नाते) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में खंड 3 (ओ) के अनुसार अपने पूरे निवल मूल्य के बराबर या उससे अधिक नुकसान होता है। "औद्योगिक कंपनी "से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो खंड 3 (ई) के अनुसार एक या अधिक औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी है।""औद्योगिक उपक्रम" को खंड 3 (च) के अनुसार किसी भी कंपनी द्वारा एक या अधिक कारखानों में चलाए जा रहे अनुसूचित उद्योग से संबंधित उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है।

22. वास्तव में एक "बीमार औद्योगिक कंपनी" एक ऐसी कंपनी है जिसके पास उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआरए) द्वारा अनुध्यात अनुसूचित उद्योग से संबंधित एक या अधिक औद्योगिक उपक्रम हैं।

23. इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य सभी बीमार कंपनियों को नहीं, बल्कि आई. डी. आर. ए. की अनुसूची में शामिल कंपनियों को पुनर्जीवित करना और उनका पुनर्वास करना है, जो संभवतः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

24. इस अधिनियम में इस बात की जांच का प्रावधान है कि क्या कोई कंपनी एक बीमार औद्योगिक कंपनी है, एक मूल्यांकन क्या इसे व्यवहार्य बनाया जा सकता है और अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ वित्तीय मामलों के लिए किसी योजना की तैयारी और मंजूरी बीमार औद्योगिक कंपनी का पुनर्निर्माण। यह एस. आई. सी. ए. अधिनियम की धारा 16,17 और 18 के अनुसार बीमार औद्योगिक कंपनी के उचित प्रबंधन, बीमार कंपनी के एक हिस्से या पूरे औद्योगिक उपक्रम के समामेलन, बिक्री या पट्टे आदि का प्रावधान करता है।

25. यह अधिनियम बोर्ड को योजना में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है-बीमार औद्योगिक कंपनी का स्थानांतरितीकर्ता कंपनी के साथ एकीकरण, ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन, शेयरधारकों के ब्याज या अधिकारों में कमी और कानूनी कार्यवाही जारी रखने के लिए, औद्योगिक उपक्रम की बिक्री या पट्टा आदि।

26. यह इस पृष्ठभूमि में है कि खंड 22, जो कानूनी कार्यवाही के निलंबन का प्रावधान करती है, अधिनियमित की गई है। जहाँ तक यह यहाँ प्रासंगिक है, यह खंड निम्नानुसार हैः

> "22. कानूनी प्रक्रियाओं, अनुबंधों, ई. टी. सी. की समाप्ति।
>
> (1) जहां किसी औद्योगिक कंपनी के संबंध में, खंड 16 के तहत जांच लंबित है, या कोई खंड 17 के तहत निर्दिष्ट योजना तैयार या विचाराधीन है या एक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन के तहत है या जहां एक औद्योगिक कंपनी से संबंधित खंड 25 के तहत एक अपील लंबित है, तो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य में कुछ भी निहित होने के बावजूद। उक्त अधिनियम या अन्य कानून के तहत प्रभावी कानून या औद्योगिक कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम औद्योगिक कंपनी के समापन के लिए या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कोई कार्यवाही या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए और धन की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी प्रतिभूति को लागू करने के लिए या किसी भी ऋण या औद्योगिक कंपनी को दिए गए अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी के लिए कोई

मुकदमा नहीं होगा या आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिवाय बोर्ड की सहमति या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण के।"

27. इस खंड को उन मौजूदा उपायों की पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया है जिनका लाभ लेनदार एक ऋणी कंपनी और उसकी संपत्तियों के खिलाफ उठा सकते हैं जो उन्हें कुर्की, नीलामी बिक्री आदि के लिए लाते हैं, जिससे एस. आई. सी. ए. के तहत इसके पुनर्निर्माण के लिए सौंपे गए अधिकारियों के लिए पुनर्निर्माण के लिए एक योजना विकसित करना मुश्किल हो जाता है।एस. आई. सी. ए. की खंड 32 के अनुसार इस खंड को एक गैर-अस्थाई खंड के रूप में भी प्राथमिकता दी गई है जो इस प्रकार हैः-

"32. अन्य कानूनों पर अधिनियम का प्रभाव

(1) इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या योजनाओं के प्रावधान प्रभावी होंगे। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) के प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद। एक औद्योगिक कंपनी या किसी अन्य साधन में जो इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी है।

(2) जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी योजना के तहत किसी बीमार व्यक्ति का समामेलन किया गया है। किसी अन्य कंपनी के साथ औद्योगिक कंपनी, आयकर की खंड 72 ए के प्रावधान अधिनियम, 1961 (1961 का 43), इन संशोधनों के अधीन रहते हुए कि उस खंड

के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का उपयोग बोर्ड द्वारा उस खंड में निर्दिष्ट निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी भी सिफारिश के बिना किया जा सकता है, ऐसे समामेलन के संबंध में लागू होगा जैसा कि वे लागू होते हैं। किसी औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ विलय।"

28. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एस. आई. सी. ए. के साथ यह खंड 1985 में अधिनियमित की गई थी।उस समय ऋण वसूली न्यायाधिकरण में एक आवेदन द्वारा से एक लेनदार द्वारा वसूली के लिए आर. डी. डी. बी. अधिनियम 1993 द्वारा बाद में प्रदान किए गए उपाय अस्तित्व में नहीं थे और न ही उन पर विचार किया गया था।एस. आई. सी. ए. में स्वाभाविक रूप से वसूली के इस तरह के तरीके का कोई संदर्भ नहीं है और न ही स्पष्ट शब्दों में ऐसी कार्यवाही पर रोक लगाने पर विचार किया गया है। हम यह हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि खंड 22 केवल बीमार कंपनी की संपत्तियों के संकट या निष्पादन के लिए कार्यवाही पर रोक लगाने पर विचार करती है और वसूली के लिए मुकदमा करती है और इसलिए आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत वसूली के लिए आवेदन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, और इसे आगे बढ़ना चाहिए। हम यह भी देख सकते हैं कि इस निवेदन को स्वीकार करने का परिणाम कि खंड 22 आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत वसूली के लिए आवेदन को प्रभावित या असमर्थनीय नहीं बना सकती है, एक विसंगति का कारण बनेगी।निवेदन यह है कि खंड 22 में कहा गया है कि केवल समापन या निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्यवाही नहीं होगी या उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जहां कोई जांच लंबित है या कोई योजना तैयार या विचाराधीन है या कोई मंजूरी योजना कार्यान्वयन के अधीन है आदि।; जबकि ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही आगे बढ़ सकती है।इसे दूसरे तरीके से कहने के लिए, कि

वसूली की कार्यवाही एक बीमार कंपनी के खिलाफ होगी, लेकिन इसमें दिए गए आदेश को औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादित नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव यह है कि कार्यवाही बिना किसी परिणाम के जारी रह सकती है।इस प्रकार कंपनी की संपत्तियों के खिलाफ कोई निष्पादन या प्रतिबंध नहीं हो सकता है लेकिन लेनदार डी. आर. टी. के समक्ष वसूली के लिए आवेदन करना जारी रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि वर्तमान विधायी योजना में इस तरह के विसंगत उद्देश्य के लिए संसद को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि संसद इसे वांछनीय समझती है तो वह स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति ला सकती है।अन्यथा भी, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए विधायी उद्देश्य को विफल किया जा सकता है यदि लेनदारों को डी. आर. टी. के आदेशों के साथ कंपनी की संपत्तियों को बोझिल करने की अनुमति दी जाती है, जबकि बी. आई. एफ. आर. यदि आवश्यक हो, तो कंपनी की संपत्तियों को पट्टे पर देकर या बेचकर कंपनी को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है, जिसके लिए एक स्पष्ट शक्ति है।

29. स्पष्ट रूप से, यह निर्धारित करने का उद्देश्य यह है कि निष्पादन और अपराध या इसी तरह या वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा, बीमार औद्योगिक कंपनी और खुद कंपनी की संपत्तियों को उसके लेनदारों द्वारा कार्रवाई किए जाने से बचाना है जो कंपनी को बंद करने या उसकी संपत्तियों के खिलाफ निष्पादन या संकट लगाने की मांग कर सकते हैं।यह कंपनी को ऐसी सभी कार्यवाही से बचाता है।यह कंपनी को धन की वसूली या प्रवर्तन के लिए मुकदमों से भी बचाता है। औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में कोई प्रतिभूति या कोई गारंटी। लेकिन जैसा कि स्पष्ट है, प्रतिरक्षा आत्यन्तिक नहीं है। ऐसी कार्यवाही जिसे कोई लेनदार स्थापित करना चाहे, बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण की सहमति से शुरू या जारी रखी जा सकती है। मूल रूप से अधिनियमित खंड में, "और धन की वसूली या

किसी भी प्रतिभूति को लागू करने के लिए कोई मुकदमा नहीं" शब्द नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन शब्दों को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। इसके बजाय यह स्पष्ट करें कि धन की वसूली आदि के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा या ऐसी कंपनी के खिलाफ झूठ बोला जाएगा या कार्रवाई की जाएगी।

30. इस समय पर, इस पर ध्यान देना उचित होगा कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। प्रादेशिक औद्योगिक बनाम एवं निवेश निगम ऑफ यू.पी. लिमिटेड और अन्य. 1 , जहां इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या खंड 22 बीमार कंपनी के गारंटरों को सुरक्षा प्रदान करती है या केवल बीमार कंपनी को। यह तर्क दिया गया था कि खंड 22 धन की वसूली के लिए या किसी औद्योगिक कंपनी को दिए गए ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी को लागू करने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकती है।यह दावा किया गया था कि यदि खंड 22 (1) के तहत अदालत द्वारा से वसूली के लिए कार्यवाही प्रतिबंधित की गई थी, तो कोई कारण नहीं था कि जब अदालत का सहारा लिए बिना कार्रवाई करने की मांग की गई थी तो सुरक्षा से इनकार कर दिया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि "कार्यवाही" और "वाद" शब्दों को अलग-अलग अर्थों के रूप में अलग-अलग समझा जाना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग अलग-अलग चीजों को दर्शाने के लिए किया गया था।न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि खंड 22 (1) केवल औद्योगिक कंपनी के खिलाफ वसूली को प्रतिबंधित करती है और वसूली कार्यवाही के खिलाफ गारंटरों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।1(2003) 4 एससीसी 305

31. कैलाश नाथ अग्रवाल (ऊपर) में इस निर्णय के बल पर यह तर्क दिया गया कि आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत दायर कंपनी के खिलाफ वसूली के लिए आवेदन, जिसके निष्पादन में अपीलकर्ता ने कंपनी की संपत्ति खरीदी थी, न तो खंड 22 के अर्थ के भीतर "कार्यवाही" थी और न ही "मुकदमा" था।इसलिए, वसूली के लिए

आवेदन में कार्यवाही खंड 22 द्वारा अप्रभावी रही।हालाँकि, हम पाते हैं कि कैलाश नाथ अग्रवाल में निर्णय अपीलकर्ता की सहायता के लिए नहीं आता है।उस फैसले में इस मामले में उठे सवाल पर विचार नहीं किया गया था।इसने एस. आई. सी. ए. की खंड 22 (1) के तहत गारंटरों को दी जाने वाली सुरक्षा के दायरे के बारे में सवाल पर विचार किया और कहा कि खंड 22 (1) के तहत गारंटरों को बीमार कंपनी से अलग कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, क्योंकि "सूट" अभिव्यक्ति का उपयोग केवल बीमार औद्योगिक कंपनियों के संबंध में किया गया था न कि गारंटरों के संबंध में। इसी तरह, संकट और निष्पादन के संबंध में "कार्यवाही" अभिव्यक्ति का उपयोग "वाद" के अलावा कुछ और दर्शाने के लिए किया जाता था।इस मामले में ऐसा कोई सवाल नहीं है।

32. जैसा कि पहले देखा गया है, खंड 22 की उप-खंड (1) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग में, यह प्रावधान है कि औद्योगिक कंपनी को बंद करने के लिए या ऐसी औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, और दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि धन की वसूली या किसी प्रतिभूति को लागू करने के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। औद्योगिक कंपनी के खिलाफ या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी के खिलाफ, बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण की सहमति के अलावा, आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

33. निस्संदेह, वर्तमान कार्यवाही अर्थात "वसूली के लिए आवेदन" को विशेष रूप से किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्यवाही के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी कार्यवाही है जिसके परिणामस्वरूप और वास्तव में कंपनी की संपत्ति के खिलाफ निष्पादन और संकट हुआ था और इसलिए इसे औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्यवाही के रूप में माना जा सकता है।हमारा विचार

है कि इस तरह का निर्माण संसद के इरादे के भीतर होगा जहां भी ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है जो उधारकर्ता की संपत्ति के बंधक या गिरवी द्वारा सुरक्षित की गई है।निश्चित रूप से, यह समझने का कोई उद्देश्य नहीं है कि संसद का इरादा था कि संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा वसूली के लिए इस तरह के आवेदन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केवल इसके निष्पादन को विशेष रूप से बाधित किया जाना चाहिए।इस संदर्भ में, यह याद रखा जा सकता है कि आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार वसूली के लिए आवेदन के माध्यम से कार्यवाही को खंड 22 में केवल इसलिए संदर्भित नहीं किया गया है क्योंकि आर. डी. डी. बी. अधिनियम तब अधिनियमित नहीं किया गया था।

बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (आर. डी. डी. बी. अधिनियम) के कारण ऋणों की वसूली की योजना और उद्देश्य

34. 1993 में, संसद ने बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993, यानी आर. डी. डी. बी. अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली को पारित किया। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दायर किए गए पंद्रह लाख से अधिक मामले और वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर किए गए लगभग 304 मामले जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की वसूली शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 5622 करोड़ रुपये का बकाया है। वित्तीय संस्थानों का 391 करोड़ रुपये का बकाया था। सार्वजनिक धन की इतनी बड़ी राशि को बंद करने से देश के विकास के लिए धन का उचित उपयोग और पुनर्चक्रण बाधित हुआ।आर. डी. डी. बी. अधिनियम इस प्रकार ऋणों की वसूली के लिए मौजूदा प्रक्रिया के कारण भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के इस तरह के ठहराव को रोकने के लिए लागू किया गया था।एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता थी जिसद्वारा से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों को बिना किसी देरी के प्राप्त किया जा सके, विशेष न्यायालयों के रूप में, जो

संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेंगे।इन न्यायालयों को अंततः जाना जाने लगा। ऋण वसूली न्यायालय के रूप में।

35. आर. डी. डी. बी. अधिनियम द्वारा अनुध्यात 'ऋण' किसी भी व्यक्ति से बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा देय के रूप में दावा किए गए दायित्व को संदर्भित करता है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित या किसी दीवानी अदालत के डिक्री या आदेश के तहत देय हो या कोई मध्यस्थता पुरस्कार या किसी बंधक के तहत और कानूनी रूप से वसूली योग्य, खंड 2 (जी) के अनुसार।वसूली के लिए खंड 3 के तहत स्थापित न्यायाधिकरण में आवेदन किए जाने की आवश्यकता थी।खंड 20 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जानी थी।निर्णय लेने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन /अपील के लिए, वसूली प्रमाण पत्र को खंड 25 के तहत अध्याय V द्वारा निष्पादित किया जाता है।प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने पर वसूली अधिकारी को खंड 25 के अनुसार प्रतिवादी की चल या अचल संपत्ति आदि की कुर्की और बिक्री द्वारा प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट ऋण की राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है।खंड 18 किसी के अधिकार क्षेत्र को वर्जित करती है। न्यायालय या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर कोई भी प्राधिकरण, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के लिए आवेदन के संबंध में।खंड 34, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, आर. डी. डी. बी. अधिनियम पर निम्नलिखित शर्तों में एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करती हैः

> "34. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें।--(1) उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी दस्तावेज में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। (2) इस अधिनियम

या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, भारतीय इकाई न्यास अधिनियम, 1963, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 और भारतीय लघु उद्योग बैंक अधिनियम, 1989 के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।"

36. यह विशेष कानून, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली से संबंधित है, ऐसे ऋणों की वसूली की प्रक्रिया को अनन्य और अद्वितीय भी बनाता है। उप-धारा (1) में गैर-अस्थाई खंड आर. डी. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों पर एक ओवरराइडिंग प्रभाव प्रदान करता है, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत है।तथापि, उप-धारा (2) आर. डी. डी. बी. अधिनियम को उसमें उल्लिखित पाँच अधिनियमों के अवमूल्यन या निरसन में अतिरिक्त बनाती है और नहीं। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948; राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951; भारतीय इकाई न्यास अधिनियम, 1963; भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 और बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985।

37. 2000 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा एस. आई. सी. ए. डब्ल्यू. ई. एफ. 17.01.2000 में उप-धारा (2) जोड़ी गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई अधिनियम, जैसा कि यहाँ, यह प्रावधान करता है कि उसके प्रावधान किसी अन्य कानून या कानूनों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि विधानमंडल का इरादा है कि ऐसा अधिनियम अन्य अधिनियमों के साथ सह-अस्तित्व में होगा।स्पष्ट रूप से ऐसे मामले में विधानमंडल का इरादा अन्य कानूनों के प्रावधानों को रद्द करने या उनसे अलग करने का नहीं है।"अपमान में" शब्द का अर्थ है "निराकरण या निराकरण में"।"

ब्लैक लॉ डिक्शनरी "अपमान" के लिए निम्नलिखित अर्थ निर्धारित करती हैः

> "बाद के अधिनियम द्वारा किसी कानून का आंशिक निराकरण या निराकरण जो इसके दायरे को सीमित करता है या इसकी उपयोगिता और शक्ति को बाधित करता है।" यह स्पष्ट है कि उप-धारा (1) में एक गैर-अस्थाई खंड है, जो आर. डी. डी. बी. अधिनियम को प्रमुख प्रभाव देता है। उप-धारा (2) ऐसे प्रबलकारी प्रभाव के लिए अपवाद की प्रकृति में कार्य करती है।इसमें कहा गया है कि यह प्रमुख प्रभाव कुछ कानूनों के संबंध में है और आर. डी. डी. बी. अधिनियम ऐसे कानूनों के अतिरिक्त होगा न कि निराकरण में।एस. आई. सी. ए. निस्संदेह ऐसा ही एक कानून है।

38. उप-धारा (2) का प्रभाव अनिवार्य रूप से एस. आई. सी. ए. के तहत प्राधिकरणों की शक्तियों को संरक्षित करने और कार्यवाहियों को बाद के अधिनियम यानी आर. डी. डी. बी. अधिनियम द्वारा ओवरराइड होने से बचाने के लिए होना चाहिए।

39. इस प्रकार, हम एस. आई. सी. ए. के तहत कंपनी के पुनर्निर्माण की कार्यवाही के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण योजना पाते हैं, जिसमें ऋणों का पुनर्निर्माण और यहां तक कि इस उद्देश्य के लिए बीमार कंपनी की संपत्तियों की बिक्री या पट्टा भी शामिल है, जो एक ओर बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में बीमार कंपनी द्वारा निष्पादित प्रतिभूति का हिस्सा हो या न हो, और आर. डी. डी. बी. अधिनियम के प्रावधान, जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली से संबंधित हैं, यदि आवश्यक हो तो दूसरी ओर बैंक या वित्तीय संस्थान से प्रभारित प्रतिभूति को लागू करना।

40. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों विशेष कानून हैं।एस. आई. सी. ए. एक विशेष कानून है, जो बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण और उससे संबंधित मामलों से संबंधित है, हालांकि यह ऋण की वसूली जैसे अन्य मामलों के संबंध में सामान्य है। आर. डी. डी. बी. अधिनियम भी एक विशेष कानून है, जो एक विशेष प्रक्रिया द्वारा से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को देय धन की वसूली से संबंधित है, हालांकि यह हो सकता है अन्य मामलों के संबंध में सामान्य जैसे कि बीमार कंपनियों का पुनर्निर्माण जो यह भी नहीं करता है विशेष रूप से व्यवहार करें अतः दोनों कानूनों का उद्देश्य अलग-अलग है।

41. यह माना जाना चाहिए कि संसद को आर. डी. डी. बी. अधिनियम, 1993 को लागू करते समय 1985 में अधिनियमित पूर्व कानून अर्थात एस. आई. सी. ए. की जानकारी थी। प्रक्रिया के टकराव को रोकने के लिए, और एक ही इकाई और उसकी संपत्तियों के संबंध में विरोधाभासी आदेशों की संभावना को रोकने के लिए, और विशेष रूप से, ऐसी बीमार कंपनी की संपत्तियों के संबंध में एक बीमार कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए पहले से ही उठाए गए कदमों को संरक्षित करने के लिए, जिन पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिभूति के रूप में शुल्क लिया जा सकता है। संसद ने विशेष रूप से उप-धारा (2) अधिनियमित की है। एस. आई. सी. ए. को निर्दिष्ट और सीमित कंपनियों के संबंध में अधिनियमित किया गया था, अर्थात वे जो आई. डी. आर. अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों के मालिक थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जबकि आर. डी. डी. बी. अधिनियम उन सभी व्यक्तियों से संबंधित है, जिन्होंने बैंक या वित्तीय संस्थान से नकद या अन्यथा ऋण लिया हो सकता है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित आदि।

42. वास्तव में, यह प्रश्न कि कौन सा अधिनियम प्रबल होगा, दोनों अधिनियमों के उद्देश्य के संबंध में विचार किया जाना चाहिए; दोनों अधिनियमों में से कौन सा

सामान्य या विशेष है; जो बाद में है। यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या उनका सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जा सकता है।

43. कहा जाता है कि जो टकराव उत्पन्न होता है वह एस. आई. सी. ए. की खंड 22 के बीच है जिसका उद्देश्य बीमार कंपनी के खिलाफ ऋण की वसूली के लिए असमर्थनीय "कार्यवाही" करना और एक ओर वसूली के लिए "वाद" करना है और दूसरी ओर आर. डी. डी. बी. अधिनियम की खंड 34 में इसके अपने प्रावधान पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है, जिसमें स्पष्ट रूप से ऋण की वसूली भी शामिल है।इस पहलू से निपटने वाले इस न्यायालय के कुछ फैसलों को राम नारायण बनाम शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी में देखा जा सकता है।दोनों गैर-अस्थाई खंडों वाले कानून, जिसमें यह प्रावधान है कि अधिनियम के विशेष प्रावधान प्रभावी होंगे (उस समय लागू किसी अन्य कानून में उसमें कुछ भी असंगत होने के बावजूद) विचार के लिए गिर गए।ये दो अधिनियम थे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 और विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951।इस न्यायालय ने बैंकिंग कंपनी अधिनियम को प्राथमिकता दी। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः-

> "7. .....इसलिए, इन दोनों अधिनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों में से एक या दूसरे के प्रबल प्रभाव को निर्धारित करना वांछनीय है, किसी दिए गए मामले में, दोनों अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति के बहुत व्यापक विचार और उसमें प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा द्वारा व्यक्त स्पष्ट इरादे पर।"

44. बाद के एक मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि दिल्ली किराया नियंत्रण द्वारा अधिनियमित कब्जे का अधिकार स्लम क्लीयरेंस अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं था और स्लम क्लीयरेंस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त

किए बिना खंड 25-बी में प्रदान किए गए तरीके से अधिकार को लागू किया जा सकता था। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब झुग्गी निकासी अधिनियम में एक गैर-अस्थाई खंड शामिल था, इस प्रभाव के लिए कि किरायेदारों को बेदखल करने की कार्यवाही की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती थी सक्षम प्राधिकारी। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम ने खंड 14-ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा मकान मालिक को आवंटित आवासीय परिसरों को खाली करने की स्थिति में तत्काल कब्जा वसूल करने का अधिकार प्रदान किया है।यह अधिकार एक गैर-अस्थाई खंड के साथ प्रदान किया गया था।यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे संघर्षों को हल करने के लिए, एक परीक्षा जो अपनाई जा सकती है, वह यह है कि बाद का अधिनियम पहले वाले पर प्रबल होना चाहिए।यह देखने के बाद कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को एक गैर-अस्थाई खंड के साथ इस ज्ञान के साथ अधिनियमित किया गया था कि स्लम क्लीयरेंस अधिनियम का ओवरराइडिंग प्रावधान पहले से ही अस्तित्व में था, बाद का अधिनियम पहले वाले पर प्रबल होना चाहिए।अधिनियम, 1958 ए. आई. आर. 1956 एससी 614:1956 एससीआर 603

45. एल. आई. सी. मे बनाम डी. जे. बहादुर 3 , इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि दो कानूनों में से कौन सा कानून अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आई. डी. अधिनियम) और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एल. आई. सी. अधिनियम) एक विशेष कानून था।सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक (सामान्य प्रावधान विशेष प्रावधानों निराकृत होना नहीं करेंगे) के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि एल. आई. सी. का कोई कर्मचारी अपनी शिकायत में आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता है, मामले का निर्णय एल. आई. सी. अधिनियम के अनुसार करना होगा। न्यायालय ने कहा कि जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के संबंध में एल. आई. सी. अधिनियम "विशेष" था।लेकिन

फिर भी, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विवादों को आई. डी. अधिनियम के तहत निपटाया जाना था जो इस तरह के विवादों को हल करने के लिए एक विशेष कानून था और यदि जीवन बीमा निगम में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो एल. आई. सी. अधिनियम को "सामान्य कानून" के रूप में माना जाना चाहिए और आई. डी. अधिनियम को "विशेष कानून" के रूप में माना जाना चाहिए।" न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-

> "52. यह निर्धारित करने में कि कोई अधिनियम विशेष है या सामान्य, ध्यान इस पर होना चाहिए मुख्य विषय-वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य।कुछ उद्देश्यों के लिए, एक अधिनियम सामान्य हो और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और हम कानून के सूक्ष्म बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर को धुंधला नहीं कर सकते हैं।कानून के अनुसार, हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें कोई निरपेक्षता नहीं है - जीवन में भी"

46. महाराष्ट्र ट्यूब लिमिटेड में। बनाम राज्य औद्योगिक और निवेश निगम। महाराष्ट्र लि. 4, दो विशेष संस्थाओं अर्थात राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एस. आई. सी. ए.) के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ।यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 1951 का अधिनियम बीमारी की स्थिति से संबंधित है, जबकि 1985 का अधिनियम बीमारी के बाद की स्थिति से संबंधित है, और इसलिए, इस बात से सहमत होना संभव नहीं था कि 1951 का अधिनियम एक विशेष क़ानून है। 1985 अधिनियम जो एक सामान्य अधिनियम है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः-

"दोनों अलग-अलग स्थितियों से निपटने वाली विशेष मूर्तियां हैं, उदाहरण के लिए, दोनों अलग-अलग स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि बीमार औद्योगिक उपक्रमों के मामलों में इसमें निहित प्रावधान 1985 अधिनियम आम तौर पर प्रबल होता और शासन करता।"

47. इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक 5 में एक बाद के फैसले में, इस अदालत ने कहा कि कंपनी अधिनियम के संदर्भ में, आर. डी. डी. बी. अधिनियम को एक "विशेष कानून" के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि दोनों कानूनों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बकाया की वसूली के संबंध में "विशेष कानून" के रूप में माना जा सकता है।बाद के एक मामले में यह सवाल विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का मुकदमा) अधिनियम, 1992 और एस. आई. सी. ए. के संदर्भ में उठा। यह तर्क दिया गया कि एस. आई. सी. ए. में निहित विशेष प्रावधानों को देखते हुए विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि एस. आई. सी. ए. की खंड 32 में एक गैर-अस्थाई खंड है, विशेष न्यायालय अधिनियम की खंड 13 में एक समान गैर-अस्थाई खंड है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः- "9... इस न्यायालय ने अनिश्चित शब्दों में निर्धारित किया है कि ऐसी स्थिति में यह बाद का अधिनियम है जो प्रबल होना चाहिए।"

48. इस न्यायालय ने विशेष न्यायालय की टिप्पणियों को इस प्रभाव से अनुमोदित किया कि यदि विधायिका बाद के अधिनियम पर एक गैर-अस्थाई खंड प्रदान करती है, तो इसका मतलब है कि विधायिका का इरादा है कि बाद का अधिनियम प्रबल होना चाहिए।इसके अलावा, यह व्याख्या का एक तय नियम है कि यदि एक निर्माण से टकराव होता है, जबकि दूसरे निर्माण पर दो अधिनियमों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जा सकता है, तो बाद वाले को अपनाया जाना चाहिए।

49. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट और उन पर भरोसा किए गए निर्णयों में इस न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि दोनों अधिनियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है।जैसा कि पहले देखा गया है, एक का उद्देश्य बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण के लिए सुधारात्मक उपाय प्रदान करना है, और दूसरे का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की त्वरित वसूली प्रदान करना है। दोनों अधिनियम इस मायने में "विशेष" हैं। हालाँकि, बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण के विशिष्ट उद्देश्य के संदर्भ में, एस. आई. सी. ए. को एक विशेष कानून माना जाना चाहिए, हालाँकि इसे ऋणों की वसूली के संबंध में एक सामान्य कानून माना जा सकता है।जबकि, आर. डी. डी. बी. अधिनियम को ऋणों की वसूली के संबंध में एक विशेष कानून माना जा सकता है और एस. आई. सी. ए. को इस संबंध में एक सामान्य कानून माना जा सकता है।इस उद्देश्य के लिए हम एल. आई. सी. बनाम विजय बहादुर (उपरोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हैं।आम तौर पर दोनों में से उत्तरार्द्ध इस सिद्धांत पर प्रबल होगा कि विधानमंडल को पता था कि उसने पहले के अधिनियम को अधिनियमित किया था और फिर भी एक गैर-अबाधित खंड के साथ बाद के अधिनियम को अधिनियमित करने का विकल्प चुना।हालाँकि, इस मामले में, आर. डी. डी. बी. अधिनियम के गैर-अस्थाई खंड में संसद का स्पष्ट इरादा हमें उस दृष्टिकोण को लेने की अनुमति नहीं देता है।यद्यपि आर. डी. डी. बी. अधिनियम बाद का अधिनियमन है, खंड 34 की उप-खंड (2) विशेष रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधान एस. आई. सी. ए. सहित उसमें उल्लिखित अन्य कानूनों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अपमान में।

50. "अपमान में नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से संसद के इरादे को व्यक्त करता है कि वह किसी भी तरह से एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों को कम या निराकृत होना नहीं करेगी।वास्तव में इसका मतलब यह होना चाहिए कि संसद का इरादा एक बीमार कंपनी

के पुनर्निर्माण के लिए एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही जारी रखने का था और उस उद्देश्य के लिए आगे यह इरादा था कि कंपनी और उसकी संपत्तियों के खिलाफ अन्य सभी कार्यवाही को लंबित रखा जाना चाहिए। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया।जबकि खंड 22 के तहत "कार्यवाही" शब्द मूल रूप से शामिल नहीं था। आर. डी. डी. बी. अधिनियम, जो अस्तित्व में नहीं था।खंड 22 आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत कार्यवाही को शामिल करती है।

51. दोनों अधिनियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है और जहां दोनों कानूनों के तहत कार्रवाई विरोधाभासी प्रतीत हो सकती है, संसद ने एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही को बुद्धिमानी से संरक्षित किया है, विशेष रूप से उप-धारा (2) के लिए प्रावधान करके, जो यह निर्धारित करता है कि बाद का अधिनियम आर. डी. डी. बी. एस. आई. सी. ए. के अतिरिक्त होगा न कि अपमान में।

52. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि इस निष्कर्ष को व्याख्या के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना जाता है, अर्थात विधानमंडल के इरादे को प्रभावी बनाना। इस मामले में कठिनाई मुख्य रूप से एस. आई. सी. ए. की खंड 22 को लागू करते समय आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत ऋणों की वसूली के लिए आवेदनों को शामिल करने के लिए संसद के इरादे को दर्शाने वाले विशिष्ट शब्दों की अनुपस्थिति में के कारण उत्पन्न हुई। जैसा कि पहले देखा गया है, इस अभावि का स्पष्ट कारण यह तथ्य है कि एस. आई. सी. ए. पहले अधिनियमित किया गया था।आर. डी. डी. बी. अधिनियम के अधिनियमन के बाद एस. आई. सी. ए. पर विचार करना इस न्यायालय का कर्तव्य है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह प्रावधान करने का सच्चा इरादा और उद्देश्य कि निष्पादन या बाधाओं या मुकदमों के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी या आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।निस्संदेह, संकीर्ण अर्थों में ऋण की वसूली के लिए एक आवेदन एक सीमित अर्थ दे सकता है अर्थात एक कार्यवाही जो दाखिल करने पर शुरू होती है

और समाप्त होती है निर्णय। हालाँकि, इस तरह के सीमित अर्थ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक का वास्तविक उद्देश्य पुनर्प्राप्ति के लिए आवेदन निष्पादन और पुनर्प्राप्ति के तार्किक अंत तक आगे बढ़ना है, जो कि निष्पादन और बाधा के माध्यम से है।इस प्रकार हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि खंड 22 आर. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई वसूली के लिए इस तरह के आवेदन को स्पष्ट रूप से शामिल करती है और इसमें हस्तक्षेप करती है। हम खुद को भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रासंगिक निर्माण के सिद्धांतों के अक्सर उद्धृत बयान की याद दिला सकते हैं। लिमिटेड और Ors.6, जहाँ इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः-

> "33. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए।वे व्याख्या के आधार हैं।यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है।इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल खाती है।एक अधिनियम की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था।इस ज्ञान के साथ, अधिनियम को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए।यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने पर अलग दिखाई दे सकते हैं।इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और यह पता लगाना

चाहिए कि प्रत्येक खंड, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और यह कहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यह पूरे अधिनियम की योजना में फिट बैठता है। अधिनियम के किसी भी भाग और अधिनियम के किसी भी शब्द को अलग से नहीं समझा जा सकता है।क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो"

53. इसके अलावा, हमने एस. आई. सी. ए. के खंड 22 के दायरे से वसूली आवेदन को बाहर करने के इरादे में कुछ भी विपरीत नहीं पाया है, वास्तव में इस तरह के बहिष्कार का कोई कारण नहीं हो सकता है क्योंकि प्रावधान का उद्देश्य एक बीमार कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करना है, ताकि बी. आई. एफ. आर. द्वारा इसके पुनरुद्धार के उद्देश्य से उनसे सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटा जा सके। पंजाब राज्य बनाम। ओकारा अनाज खरीदार सिंडिकेट Ltd.7, न्यायालय ने अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को संरक्षित करने के महत्व को स्पष्ट किया और कहाः-

"14. .....इसलिए हम इस आधार पर अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या सरकार किसी क़ानून द्वारा बाध्य है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि क्या यह उस प्रावधान में स्पष्ट रूप से नामित है, जिसके बारे में यह तर्क दिया गया है कि वह इसे बाध्य करता है, या क्या यह "क़ानून की शर्तों से स्पष्ट है कि यह विधायिका का इरादा था कि वह बाध्य होगी", और यह कि बाध्य करने का इरादा स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि क्या क़ानून का लाभकारी उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा जब तक कि सरकार बाध्य नहीं थी।"

54. संदर्भ का उत्तर देने के बाद, हमारा मानना है कि एस. आई. सी. ए. के प्रावधान, विशेष रूप से खंड 22, आर. डी. डी. बी. अधिनियम में ऋणों की वसूली के प्रावधान पर हावी होंगे। इन परिस्थितियों में, जैसा कि इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले ही निर्देश दिया है, दिल्ली उच्च न्यायालय के 23.02.06 दिनांकित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।जहां तक रिट याचिकाओं का संबंध है, चाहे वह इस आधार पर हो कि एस. आई. सी. ए. की खंड 22 आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है या क्या आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही समाप्त होने के बाद से अपीलकर्ता कंपनी को एस. आई. सी. ए. का संरक्षण उपलब्ध नहीं है, रिट याचिकाओं को खारिज करना होगा और तदनुसार खारिज कर दिया जाएगा।वर्तमान अपील की अनुमति है।

निधिजैन अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।